(h3/1700/vb-ru)

1700 बजे

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत ही अच्छा बिल है, इसका सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बिल पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसके संबंध में केवल दो-तीन बातें मैं बोलना चाहूँगा।

मैं गांव से आता हूँ। वहाँ जो घटनाएँ हो रही हैं, उनको मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहूँगा। यह बिल 'स्टार्ट अप' और 'इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' से जुड़ा है। लेकिन जब हमारे गांव का नौज़वान पैसा लेने के लिए बैंक में जाता है तो पैसे नहीं मिलते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में बैंकों में 4650 करोड़ रुपये एफडी है और 550 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। वहाँ का पैसा मुम्बई-कोलकाता हेड ऑफिस भेजा जाता है। यह पैसा तमाम बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है और वे लोग उसे किसी न किसी तरह से एनपीए बना लेते हैं।

इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम हमारे गांव के बैंकों में जो पैसे हैं, वह हमारी एफडी है। उसमें से ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे गांव के नौज़वानों को दिया जाए, ऐसा प्रयोजन किया जाए। वे 'स्टार्ट अप' में भाग लेकर वहाँ छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करके आगे बढ़ सकें। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है। यही एनाउंसमेंट भी हुआ है। लेकिन वहाँ ठीक तरह से पैसे नहीं दिये जा रहे हैं।

नेशनलाइज्ड बैंकों में एजेंट्स काम कर रहे हैं। एजेंट्स के माध्यम से उनको बताया जाता है कि फलां उद्योग में तुम्हें दस लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी। वे कहते हैं कि तुम मुझे दो-ढाई लाख रुपये रिश्वत दे दो, तो हम तुम्हारा लोन पास करेंगे। अन्यथा कोई न कोई लैकुना निकालकर उनको लोन नहीं दिया जाता है।

कुछ छोटी-मोटी फाइनेंस कम्पनियाँ बनायी जाती हैं और हमारे यहाँ किसानों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर उनको लुभाया जाता है। इससे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और

बिहार की महिलाएँ ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि वे चुपके से पैसे जमा करना चाहती हैं। कोई एजेंट आता है और 15-18 पर्सेंट ब्याज की बात कहकर उनके पैसे ले जाता है, बाद में वह कम्पनी गायब हो जाती है और उनके पैसे डूब जाते हैं। वे औरतें किसी से कह भी नहीं पाती हैं।

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में बड़े-बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें लगभग ढाई लाख रुपये होती है। उन कम्पनीज़ के डायरेक्ट पाँच-पाँच लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं। उनका क्वालीफिकेशन एसएससी या इंटरमीडिएट ही होता है। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि वे क्वालीफिकेशन के हिसाब से ही अपनी सैलरी ले सकें, नहीं तो वे लोग पब्लिक के पैसे को लूट रहे हैं।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ क्योंकि शेष बातें डिटेल में हो चुकी हैं।

धन्यवाद।

(इति)

1703 hours

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, this Bill is, of course, the need of the hour. If we look into the background of the case, you may find that Companies Act, 2013 was really a revolutionary and significant legislation which we had in the history of company laws.

We really had high hopes and we all know that in the present scenario, this kind of a legislation is having its relevance. We all know that India is becoming an international destination of investment. It is our duty to remove all the hardships and ambiguity in the way of implementing various causes of the Companies Act.

Similarly, corporate governance is also coming in a big way in India. We should give more attention and emphasis there also. As regards amendment in the CSR, it was a progressive legislation which we had in the Companies Act. I think, we must concentrate and pay more attention there also.

We have many other areas which need to be addressed. We all know that as far as this Bill is concerned, it made the companies more accountable in relation to structuring, disclosure and compliance requirements. In that way, it is the most welcome step.

The Companies Act, 2013 limits the number of intermediary companies through which investment can be made. Similarly, it also limits the number of layers of subsidiaries in a company to have this kind of an investment. This amendment makes it mandatory that the

technical member must at least be at the level of an Additional Secretary.

It is true that this legislation is intending to address the difficulties faced by the stakeholders and improve ease of doing business in our country.

(j3/1705/rp-pc)

In a way, these proposals are giving clarification and removing ambiguity. This legislation is a most welcome step.

I would only like to say two points and they should be discussed in detail considering the timeframe. I do not want to say much on this. The first point is regarding the role of independent directors as per the Companies Act. It is also a most welcome amendment. As per the Act, 2013, the role of independent director was well-explained. It was brought with a very good intention. It helps the companies to protect the interest of minority shareholders and ensure that the Board does not favour any particular stakeholder. The role of the independent directors is very relevant. It ensures clean governance among the corporates. In that way, it was a very important piece of amendment in the Companies Act.

There are certain essential qualifications for independent directors. What are those qualifications? He should not be a promoter of the company. He should not have any kind of special interest in the economic affairs of the company. He should not have any kind of financial relationship with the company. None of his relatives has any

kind of financial interest in the company. He is having completely independent nature of assignment as an independent director.

As far as this piece of legislation is concerned, my apprehension is this. I would like to know whether the independence of the independent directors is diluted or not. The hon. Minister is aware of all these things. I would, once again, like to know from him whether the independence of the independent directors will be encroached upon through this amendment. That is one thing.

At the end, I would like to say something about CSR. By the introduction of CSR, India may, perhaps, be a model to the entire world. CSR was a very progressive and revolutionary measure which we had taken. Unfortunately, CSR policy was not implemented properly. Some industrial heads are diluting it. In the proposed amendments, there is a provision for that. We are giving exemption to certain categories. I would request the hon. Minister to take such things into consideration. Any kind of dilution of CSR activities should not be there. CSR should be adhered to properly.

I would, once again, like to appeal to the hon. Minister to take these two things into consideration.

With these few words, I conclude my speech. Thank you very much.

(ends)

1708 बजे

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति जी, आपने मुझे कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो यह कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में कंपनियाँ व्यापार को सरल बनाने के लिए और देश की प्रगति में हाथ बँटाने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन आज उनका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, वह चिंता का विषय है। इस उद्देश्य से कि लोगों के लिए व्यापार करना सरल हो, इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। इस संशोधन को इसलिए लाया गया है ताकि कंपनियाँ आर्थिक अनियमितताएं एवं दुरूपयोग न कर सकें। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

मान्यवर, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि कंपनियों द्वारा 2 पर सेंट सी.एस.आर. फंड खर्च करने का एक निश्चित नियम बनाया गया है, लेकिन कंपनियाँ इस सी.एस.आर. फंड से कोई खर्चा नहीं करती हैं। मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति का सदस्य हूँ। अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने देश भर में उनको प्रेरित किया, कि वे वहाँ खेलों में खर्चा करें और खेलों को बढ़ावा दिए जाने के ऊपर खर्चा करें। इस पर हम लोगों ने पूरे देश में कई बैठकें की हैं। इन बैठकों में हमने उद्योगपतियों और बैंक के लोगों को भी बुलाया था, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं इसे लगातार 3 सालों से देख रहा हूँ।

(k3/1710/mz-rcp)

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे कृपया इस मामले को इन्श्योर करें। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से भी कंपनियों को एक निर्देश जाना चाहिए। हम लोगों के सामने भी वे निर्देश देने का काम करते हैं। हम सब लोग आग्रह करते हैं, लेकिन वे सी.एस.आर. फण्ड को खर्चा नहीं करते हैं। आज तमाम देश की जो स्थितियां है, उन कंपनियों के सहयोग की जरूरत है, लेकिन फिर भी चाहे बात उसमें खेल-कूद को बढ़ावा देने की हो या कहीं जैसे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का विषय हो, इसमें उनको

खर्चा करना चाहिए। कम से कम इसमें ऐसा प्रावधान जरूर हो, जिससे कि उन पर बंधन लगाने का काम हो कि वे सी.एस.आर. फण्ड को ठीक से खर्चा करें। उनको दो परसेंट खर्च करने के लए निश्चित ही कहा ही जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

दूसरा यह कि जैसा मेरे अन्य साथियों ने भी बात कही है कि जो छोटी-छोटी कंपनियां गरीबों का पैसा लेकर भाग जाती हैं। उसमें जो तमाम, वर्ष 2013 में जो प्रावधान था, सदन में भी इस पर चर्चा हुई। लेकिन इस पर अंकुश लगने का काम नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस बिल में निश्चित रूप से उस बात को जोड़ा जाएगा। वैसे तो वे कंपनियां स्थापित ही न हों, उनको लाइसेंस इश्यु करने के कड़े प्रावधान हों। उनके लिए शर्तें रखी जानी चाहिए, तभी उनको लाइसेंस देना चाहिए। छोटी-छोटी चिट-फण्ड कंपनियां भी लोगों का धन हड़प कर भागने का काम करती हैं। वास्तव में यह बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि इस बिल में उसे जोड़ा जाएगा। ऐसी कंपनियों के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कंपनियां पैसे लेकर भाग न सकें।

माननीय सभापति (श्री हुकुम सिंह) : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : दूसरा यह कि दिवालिया कानून, वास्तव में जो कंपनियां अपने को दिवालिया घोषित करके शेयरधारकों का पैसा हड़पने का काम करती हैं। उसमें समय-समय पर संशोधन हुए हैं। उसके लिए तमाम समितियां भी बनाई गई हैं, लेकिन उसमें भी अभी अंकुश लगने का काम नहीं हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी ऐसे कड़े प्रावधान होने चाहिए। इस दिवालिया कानून को और भी सख्त बनाने का काम होना चाहिए। अभी जैसा मेरे कुछ साथी भी कह रहे थे कि कंपनियां बनाकर अवैध पैसे को सफेद करने का काम किया जाता हैं, जैसे तमाम प्रकरण आए हैं और तमाम जांचें भी हो रही हैं। सी.बी.आई. इन्क्वायरी भी हो रही है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम कैसे इन पर अंकुश लगाने का काम करें कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध धन को वैध करने का काम न किया जाए। उस पर भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिससे ये कंपनियां अपने

उस अवैध पैसे को वैध न कर सकें। तमाम समितियों का भी गठन किया गया था, दिवालियापन सुधार समिति, सी.एस.आर. संबंधी सभी उच्चस्तरीय समिति बनायी गयी थी। जो सलाह आई हैं, उन सलाह को ठीक से लागू करने इन बातों का ध्यान दिया जाए। मैं आज यही बातें कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Before I invite the hon. Minister, I want to make a small comment. No doubt, the debate was very fruitful. There were certain Members who had pointed out some questions. They wanted reply from the Minister. I have noted down their names also and their questions also. But, fortunately or unfortunately, luckily or by chance, they are not present here. They expected reply from the Minister. I do not know whether they will switch on their TVs at their residences or some other place, but they are not here. Anyway, this is the situation which I have pointed out before you.

Now, the hon. Minister.

(l3/1715/bks-smn)

1715 बजे

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, धन्यवाद। कंपनीज़ अमेंण्डमेंट बिल, 2016 पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है। इस चर्चा में 18 लोगों ने भाग लिया है। कॉंग्रेस के बहुत ही विद्वान साथी प्रॉफेसर के.वी. थॉमस साहब ने इस चर्चा को प्रारंभ किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और जो कुछ बिंदु आए हैं। वह मुझे लगता है कि हमने ऑफीशियल अमेंडमेंट मूव किए हैं, वे शायद नहीं देख पाए होंगे, इस वजह से आए होंगे। जैसे दो बिंदुओं पर बहुत से लोगों ने चर्चा की, करीब-करीब सभी ने चर्चा की है। restriction on layers of companies, allowing unrestricted object clause for companies.इन दो बिंदुओं पर बहुत चर्चा की और इसके अलावा सी.एस.आर. पर भी बहुत चर्चा की। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि ये जिन दो बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, I propose to drop this because official amendments have been moved. Already our hon. Minister has moved official amendment for that. The official amendment, therefore, should satisfy the concern of the above matter raised by some of the Members. इस संबंध में मेरा पहला कमेन्ट यह है। दूसरा सी.एस.आर. के बारे में भी करीब-करीब सभी लोगों ने चर्चा की है। कंपनीज एक्ट की धारा 135 सी.एस.आर. की परिभाषा को परिभाषित करती है और सैक्शन 134/3 यह प्रावधान करता है कि ऐसी कंपनियां जो सैक्शन 135 में एलिजिबल हैं, वे अपने प्रोफिट का दो परसैन्ट खर्च करेगी और सभी मैम्बर्स ने यह कहा कि मंत्रालय इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने नोटिसेज दिये हैं, कुछ कंपनियों ने जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन सैक्शन अलाऊ किया है। हमने कार्रवाई प्रारम्भ कर दी हैं। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी सी.एस.आर. के बारे मे डाउट है, वे मंत्रालय में भी जाकर चर्चा कर सकते हैं। यह पहली

ऐसी सरकार है, जिन्होंने सी.एस.आर. में खर्चा करना शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी है।

दूसरा एक विषय बार-बार आया कि 2013 का जो एक्ट था, उसके कई सैक्शन का राजीव सातव साहब भी जिक्र कर रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख तक कंपनीज एक्ट, 2013 के खाली तीन सैक्शंस हैं, जो कमेन्स नहीं हैं, बाकी सारे हो गये। यह 184 का फिगर आप कहां से लाये, मुझे जानकारी नहीं हैं...(व्यवधान) आप शायद पुराना बिल पढ़ रहे होंगे।...(व्यवधान) उसे इंट्रोड्यूस हुए भी महीनों हो गये हैं। इसके अलावा प्रो.सौगत राय समेत करीब-करीब सभी सदस्यों ने जिक्र किया और जो हमारे पुराने साथी श्री निशिकान्त दुबे हैं, जो उस कमेटी के बहुत पुराने साथी हैं, शायद वह परमानेन्ट सदस्य हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर रहा था। ...(व्यवधान) 15वीं लोक सभा में भी आप फाइनेंस कमेटी के सदस्य थे। एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. ये 1 जून, 2016 से ऑपरेशनल हैं। ...(व्यवधान) Yes Sir, it is operational. आप कभी जाकर देखिये, जो हमारा आर.ओ.सी. का दफ्तर है, जो आर.डी. का दफ्तर है, उसके आसपास देखिये, एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. चालू हैं, हां उसमें कुछ स्टाफ की कमी है। ...(व्यवधान) ये फंक्शनल हैं। I can tell that it is functional in your State also. लेकिन आपने कहा चालू नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये फंक्शनल हैं। मैं खुद एज ए मिनिस्टर जाकर आया हूं। कई जगह हाई कोर्ट यह कहता है कि एल.सी.एल.टी. जहां हमारा हाई कोर्ट स्थित है, यहां होना चाहिए, वह कार्रवाई भी सरकार कर रही है। मुझे यही इनिशियल कमेन्ट्स करने थे, उसके बाद जो दो-तीन बिन्दु आए हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। थॉमस साहब ने जिक्र किया कि आपने 2013 के एक्ट के उद्देश्य को डाइल्यूट कर दिया, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया है। जो आपने टू लेयर और ऑब्जैक्ट क्लाज का जिक्र किया, वह मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल अमैंडमैन्ट में जो आपका कंसर्न्ड है, उसे हमने इस अमैंडमैन्ट के माध्यम से हल किया है।

इसके अलावा आपने जिक्र किया कि 8 नवम्बर के डीमोनेटाइजेशन के बाद कंट्री को क्या फायदा हुआ। इस बिंदु का और कई माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि इसके कई फायदे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक फायदा गिनाता हूं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में 91 लाख नये करदाता जुड़े हैं, यह देश को डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ हुआ है।

(m3/1720/gg-mmn)

टैक्स बेस बढ़ेगा तब आपके संसदीय क्षेत्र में पानी के लिए पैसा मिलेगन्? तब आपके संसदीय क्षेत्र के स्कूलों के लिए कक्षाएं बनेंगी? तब आपके यहां, जिनके सर पर छत नहीं हैं, उन सबको छति मिलेंगी? डीमॉनिटाइज़ेशन के बाद टैक्स बेस बढ़ा है, ये आंकड़ें बोलते हैं। ...(व्यवधान) हमारे दल की तरफ से किरीट सोमैया साहब बोल रहे थे और उन्होंने कुछ जिक्र किया है, एक्स डिप्टी सी.एम. महाराष्ट्र और उस बारे में, आपने कहा है कि पचास की लिस्ट है, आप लिस्ट दे दीजिए, जो एज़ पर लॉ होगा, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यह सरकार ईमानदार लोगों के पक्ष में खड़ी है। आपने सी.ए. डे पर माननीय प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना होगा, जिसका जिक्र राजीव जी कर रहे थे। उस भाषण का सार क्या है? राजीव जी, उस भाषण का सार यह है कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और ईमानदारों के पक्ष में है। यही तो सार है उसका और कोई सार ही नहीं है। इसलिए किरीट जी, आपने जो चिंता प्रकट की है, उसका भी मुझे लगता है कि जल्द ही समाधान होगा।

एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब ने एक बड़ा विषय रखा और आपने इन योजनाओं को स्लोगन बता दिया। You are a very senior Member and I think you are the best parliamentarian also. डिबेट भी आप बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन यह स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, क्लीन इण्डिया, मुद्रा ये सब स्लोगन हैं क्या? एन.के. प्रेमचंद्रन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकेले मुद्रा में 7 करोड़ 78 लाख लोगों को लोन दिया है। मैं कल ही स्टैण्ड अप इण्डिया का

रिव्यु कर के आया हूँ। 40 हज़ार के आस-पास लोगों को, एस.सी., एस.टी. और महिला एंटरप्रिन्योर जो नए बने हैं, जिनको दस लाख रूपये से ले कर एक करोड़ रूपये का लोन मिल रहा है। ये योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। जब धरातल पर ये योजनाएं उतर रही हैं और तब ये स्लोगन नहीं हैं, ये भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली योजनाएं हैं। एक जिक्र आया कि एनएसीएल, पीएसीएल और एल्डर फार्मा का जिक्र आया। हमारे अरूण जेटली साहब सही कह रहे हैं कि ये सब आपकी विरासत है, जो हमें मिली है और हम इसको हल कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि एनएसीएल के केस में एक मीटिंग महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ हुई है, किरीट जी के पत्र इस संबंध में बहुत आते रहते हैं। जो छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा वापस दिलाने में यह सरकार दृढ़ संकल्प है। चाहे पीएसीएल का इश्यु हमारे सुभाष बहेड़िया जी ने उठाया हो।

सभापति जी, पीएसीएल में लोढा कमेटी बनी हुई है। एल्डर फार्मा का इश्यु आपने उठाया है। शारदा हो, रोज़ वैली हो चाहे जो भी हो, हमारी सरकार का स्पष्ट मंत्र है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कि ये जो छोटे-छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने भरोसा कर के कैपिटल मार्केट में अपना पैसा जमा किया है, उनको राहत देनी है और मैं आपके माध्यम से जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि इनको राहत देनी है। इसीलिए भरोसा इस सरकार के प्रति बढ़ा है।

सभापति जी, अभी-अभी ओईसीडी एक सर्वे रिपोर्ट आई है। जिसमें कहा गया है कि भारत के 73 प्रतिशन नागरिकों ने जो सरकार चल रही हे, उस पर भरोसा किया है, जो कि सबसे ज्यादा है और विश्व में फर्स्ट है, हमारे बाद विकसित देश हैं तो यह भरोसे की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी लोढा कमेटी की भी रिपोर्ट आई हुई है, अलग से भी मंत्रालय काम कर रहा है, एसएफआईओ भी काम कर रहा है, ई.डी. भी अपने काम में लगी हुई है, सीबीआई भी काम कर रही है। लगातार छोटे निवेशकों के पक्ष में यह सरकार खड़ी है। अभी एक विषय आया कि कैपिटल मार्केट में ब्लैक करने वाली कंपनियां हैं। क्या बात कर रहे हो साहब? कैपिटल मार्केट इस देश की हैल्थ होती है।

(n3/1725/cs-san)

आपने कहा कि इसमें छोटे निवेशकों के प्रति भरोसा घटा है। अगर निवेशकों का भरोसा घटता, तो कैपिटल मार्केट का सेंसेक्स 32 हजार को पार नहीं करता। यह 32 हजार को पार कर रहा है और स्टे कर रहा है। जब 31 हजार को पार किया था, तो बहुत से लोगों ने, जो फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के एक्स्पर्ट हैं, उन्होंने कहा कि यह टेम्परेरी फेज है, 31 हजार पर स्टे किया, 32 हजार क्रॉस कर दिया और स्टे कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल मार्केट में भारत की हेल्थ ठीक हो रही है और यह इसे दर्शा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन विषयों को और टच करना चाह रहा हूँ। शायद भर्तृहरि महताब साहब ने कहा कि इकोनॉमी की साइज सिकुड़ रही है। आपने यह भी कहा कि बार-बार अमेंडमेंट क्यों आ रहे हैं। देखिए, वर्ष 2013 का बिल, आप साक्षी हैं, रात को यहाँ बहुत देर तक बैठना पड़ा था, शायद 10 बजे गये होंगे और उसके बाद कितने लोगों ने प्रतिवेदन दिए, बहुत लोगों ने प्रतिवेदन दिए। हमारे कोरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में सचिव स्तर की जो कमेटी बनी, उसने सुझाव लिए। जब राज्य सभा में यह बिल चर्चा में आया तो राज्य सभा ने कहा कि कांप्रिहैंसिव अमेंडमेंट बिल लाइए, इसलिए जो कमेटी बनी, फाइनेंस कमेटी में यह गया और यह कांप्रिहैंसिव अमेंडमेंट बिल है। राज्य सभा में चर्चा के दौरान यह विषय आया, इसलिए हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। वर्ष 2015 में हमने अमेंडमेंट किया। राज्य सभा में चर्चा के बाद यह एक विषय आया, उसके बाद यह बिल ला रहे हैं। हम यह बिल अपनी मर्जी से नहीं ला रहे हैं, जो सदस्य सुझाव देते हैं, जो संसद सुझाव देती है और जो कमेटी सुझाव देती है, उसके आधार पर हम यह कांप्रिहैंसिव बिल लेकर आए हैं। कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसकी ऑलमोस्ट ऑल रिकमेंडेशंस हमने इसमें मंजूर की हैं, स्वीकार की हैं और जो थोड़ी-बहुत रह गई हैं, उनको अमेंडमेंट के माध्यम से ला रहे हैं।

मैं इकोनॉमी के साइज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अभी एक सर्वे आया है। आपने भी उस सर्वे को पढ़ा होगा। वह सर्वे हमने नहीं किया है। वेस्टर्न वर्ल्ड की एक एजेंसी है, जिसने इस सर्वे को किया है। वे कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी की साइज वर्ष 2030 तक

इतनी हो जाएगी कि वह चार डेवलप्ड देशों को क्रॉस करेगी। वह जापान, जर्मनी, फ्रांस, यू.के. को क्रॉस करेगी और India will be the third largest economy by 2030. भर्तृहरि महताब साहब सिकुड़ कहाँ रही है। जितने हम इकोनॉमिक रिफार्म के...(व्यवधान) शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : दिसंबर, 2016 के बाद ये जो पिछले पाँच-सात महीने हो गए हैं, including July, the credit outgo from banks has come down to five per cent, which is the lowest in the last 60 years. यही बात मैंने कही, यही उदाहरण मैंने दिया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपने इसके साथ-साथ इकोनॉमी की भी बात की कि वह सिकुड़ रही है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is an indication.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : भर्तृहरि महताब साहब, मैं आपको बताता हूँ। यह 2017 का वर्ष है और वर्ष 2017 का जब भी कोई असेस्मेंट करेगा, इतिहासकार, प्लानर या हमारी नीति-निर्धारण करने वाले लोग असेस्मेंट करेंगे, तो यह 2017 का वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष कहलायेगा। हमने वर्ष 2016 में 8 नवम्बर को डीमोनेटाइजेशन किया। वर्ष 2017 के जनवरी से यह देश तेजी से डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ा। उसके बाद हमने यूनियन बजट 28 फरवरी से एक फरवरी किया। उसके बाद हमने रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज किया। उसके बाद हमने फाइनेंस बिल पहली बार देश के इतिहास में 31 मार्च तक पास कर दिया और एक अप्रैल को राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को खर्चे करने के लिए अधिकृत कर दिया। उसके बाद जीएसटी इस देश में एक जुलाई से लागू कर दिया और यह कंपनी बिल का भी अमेंडमेंट आज यह सदन कर रहा है। मुझे लगता है कि यह 2017 का वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष होगा। जब यह आर्थिक सुधारों का वर्ष होगा, तो इकोनॉमी की साइज निश्चित रूप से भर्तृहरि महताब साहब बढ़ेगी, मैं यह कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। एक

विषय आधार का आया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। मैं भर्तृहरि महताब साहब आपको कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है, जिनमें ऑन गोइंग स्कीम्स में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके रोकने का प्रयास किया है।

(o3/1730/hcb/ak)

जैसे चंडीगढ़ कैरोसीन जा रहा था। अगर हम टैक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते तो हम कहते कि आपके पास तो गैस है, आप कैरोसीन क्यों ले रहे हैं? जब पहले कभी कैरोसीन बंद करते थे, कुछ सरकारों ने करने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने कहा कि आप तो छोटे लोगों का हक मार रहे हो। जब हमने टैक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो चंडीगढ़ कैरोसीन फ्री हो गया। ऐसा करके इस सरकार ने अलग-अलग योजनाओं में मोदी जी के नेतृत्व में 57 हजार करोड़ रुपये ऑनगोइंग स्कीम्स में बचाए हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह कंपनीज़ अमैंडमैंट बिल 2016 सबके साथ चर्चा के बाद आया है। सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। हमने सब सुझाव नोट भी किये हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन इस बिल को पास करने की पूरी व्यवस्था करे, कृपा करे ताकि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी का साइज़ जो वैस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने तय की है और जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना है कि भारत 2022 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाए, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है, यह पास करने की अपील करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the Bill further to amend the Companies Act, 2013, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2

Amendments made:

Page 2, *after* line 32, *insert*—

'(ixA) in clause (72), in the proviso, in clause (A), *after* the words "State Act", the words "other than this Act or the previous company law" shall be *inserted;'.* (3)

Page 2, line 39, for "a company", substitute "the company". (4)

Page 2, *after* line 39, *insert*--

'Explanation. -- For the purpose of this clause, "the investing company or the venturer of a company" means a body corporate whose investment in the company would result in the company becoming an associate company of the body corporate.'. (5)

Page 3, *for* lines 3 to 7, *substitute*--

'(xii) in clause (87), in sub-clause (ii), for the words "total share capital", the words "total voting power" shall be substituted.'. (6)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: There are Amendment Nos. 50 and 51 given by Shri N. K. Premachandran. Are you moving your Amendments?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"Page 1, line 17,--

omit "the arrangement have". (50)

"Page 2, line 11,--

for "in consultation with"

substitute "with the approval of." (51)

I have moved Amendment Nos. 50 and 51 to Clause 2, that is, 'in consultation with' the Central Government. I would like to have the amendment with the approval of the Central Government in respect of instruments, which are to be signed by the concerned people.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put Amendment Nos. 50 and 51 to Clause 2 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4

Amendment made:

Page 3, *for* lines 22 to 46, *substitute*—

'4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (5), for clause (i), the following shall be substituted, namely:-

"(i) Upon receipt of an application under sub-section (4), the Registrar may, on the basis of information and documents furnished along with the application, reserve the name for a period of twenty days from the date of approval or such other period as may be prescribed:

Provided that in case of an application for reservation of name or for change of its name by an existing company, the Registrar may reserve the name for a period of sixty days from the date of approval."' . (7)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: There are Amendment Nos. 52 and 53 given by Shri N. K. Premachandran. Are you moving your Amendments?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving Amendment Nos. 52 and 53 to Clause 4.

I beg to move:

"Page 3, line 28,--

after "specific"

insert "lawful". (52)

"Page 3, lines 35 and 36,--

for "such other period as may be prescribed"

substitute "forty-five days from the date of the application." (53)

The hon. Minister has not responded to the query or clarification made by us regarding the Object Clause in the Memorandum of Association. This should be specific and lawful, but unfortunately the Minister has not responded to it. Most of the Members from this side have … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He has already spoken on it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Okay, Sir. I am moving it because 'specific' and 'lawful'. So, I would like to add the term 'lawful' also.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put Amendment Nos. 52 and 53 to Clause 4 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

(p3/1735/spr-rv)

Clause 7

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"Page 4, line 7, -

for "employee"

substitute "director". " (54)

This is a very important amendment to Section 26 of the Act, that is, an instrument has to be attested by any employee. How can it be possible?

My amendment is, instead of employee, let it be the director of the company. It is a material amendment that is to be incorporated. That is why I have moved it.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No.54 to clause 7 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8

Amendment made:

Page 4, *for* line 18*, substitute-*

"(ii) clauses (a), (b) and (d) shall be *omitted*.". (8)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 8, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clauses 9 to16 were added to the Bill.

Clause 17

Amendment made:

Page 7, *for* lines 5 to 7*, substitute-*

`17. In section 76A of the principal Act,-

(a) in clause (a), *for* the words, "one crore rupees", the words "one crore rupees or twice the amount of deposit accepted by the company, whichever is lower" shall be *substituted;*

(b) in clause (b),-

(i) *for* the words, "seven years or with fine", the words "seven years and with fine" shall be *substituted;*

(ii) the words "or with both" shall be *omitted.*'. (9)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clauses 18 to 20 were added to the Bill.

Clause 21

Amendment made:

Page 7, *for* lines 23 and 24*, substitute-*

`21. In section 89 of the principal Act,-

(i) in sub-section (6), the words and figures, "within the time specified under section 403", shall be *omitted;*

(ii) in sub-section (7), *for* the words and figures, "under the first proviso to sub-section (1) of section 403", the word "therein', shall be *substituted;*

(iii) *after* sub-section (9), the following sub-section shall be *inserted,* namely:-'. (10)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 21, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill.

Clause 22 was added to the Bill.

Clause 23

Amendments made:

Page 9, lines 9 and 10, *for* "One Person Company and small company", *substitute* "One Person Company, small company and such other class or classes of companies as may be prescribed.". (11)

Page 9, *after* line 14 *insert-*

(iii) in sub-section (4), the words and figures, "within the time as specified, under section 403", shall be *omitted;*

(iv) in sub-section (5), *for* the words and figures, "under the section 403 with additional fees", the word "therein', shall be *substituted*.'. (12)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 23, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clauses 24 to 27 were added to the Bill.

(q3/1740/sr-my)

Clause 28

Amendment made:

Page 9, lines 42 and 43, *for* "not less than ninty-five per cent.", *substitute* "majority in number of members entitled to vote and who represent not less than ninety-five per cent.". (13)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That clause 28, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

Clause 29 was added to the Bill.

Clause 30

Amendments made:

Page 10, *after* line 11, *insert* –

'(i) in sub-section (1), the words and figures "within the time specified under section 403" shall be *omitted;'.* (14)

Page 10, *for* line *12, substitute* –

'(ii) in sub-section (2), --

(a) *for* the words and figures "under section 403 with additional fees", the word "therein" shall be *substituted;*'. (15)

Page 10, line 13 *for* "(a)", *substitute* "(b)". (16)

Page 10, line 15 *for* "(b)", *substitute* "(c)". (17)

Page 10, line 17 *for* "(ii)", *substitute* "(iii)". (18)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandranji, are you moving your amendments no. 55 and 56?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 30, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: I have already put the question.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My point of order is under Rule 331N of the Rules of Procedure and also under Rule 376 of the Rules of Procedure. Kindly have a hearing. There are so many other motions that are also coming. I would like to highlight my point. The hon. Minister has circulated 43 amendment proposals out of which five

new clauses also have to be incorporated – Clauses 47A, 73A, 75A, 78A and a New Provision Clause 88. My point is, out of these 43 amendments, five new clauses have to be incorporated. This Bill had been referred to the Standing Committee. The Standing Committee had a detailed scrutiny of almost all the provisions. But, unfortunately, these five clauses have not been scrutinized by the Parliamentary Standing Committee. By virtue of Rule 331N of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha:

> "The report of the Standing Committees shall have persuasive value and shall be treated as considered advice given by the Committees."

In this case, the Standing Committee had a detailed scrutiny and the Company Law Committee has given the recommendations. All these five amendments come out of all these things. My point is, it is not proper – let me conclude – to suspend Rule 80 (i) by virtue of Rule 388 because the Standing Committee has not considered these five new clauses. That is my point of order. Kindly give the ruling.

HON. CHAIRPERSON: Please refer to Rule 376. It says that a point of order is not point of privilege when a question on any motion is being put to the House. I have told you earlier also.

(r3/1745/ub-cp)

The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 30A

Amendment made:

Page 10, *after* lines 25, *insert*-

Amendment of section 121.

'**30A.** In section 121 of the principal Act,-

(i) in sub-section (2), the words and figures "within the time specified, under section 403" shall be *omitted*;

(ii) in sub-section (3), for the words and figures "under section 403 with additional fees", the word "therein" shall be *substitued*.;'. (19)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That new clause 30A be added to the Bill".

The motion was adopted.

New clause 30A was added to the Bill.

Clause 31

Amendment made:

Page10*, for* lines 26 and 27, *substitute-*

'**31.** In section 123 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a),-

(A) for the words "both; or", the word "both:" shall be *substituted;*

(B) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in computing profits any amount representing unrealised gains, notional gains or revaluation of assets and any change in carrying amount of an asset or of a liability on measurement of the asset or the liability at fair value shall be excluded; or";

(ii) in the second proviso, *for* the words "transferred by the company to the reserves", the words "transferred by the company to the free reserves" shall be *substituted;*

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-'. (20)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That clause 31, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 31 as amended was added to the Bill.

Clause 32

Amendment made:

Page 10, line 50, *after* "subsidiary or subsidiaries", *insert* "and associate company or companies". (21)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That clause 32 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 32 as amended was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

Clause 34

Amendment made:

Page 11*, for* lines 15 to 17, *substitute-*

'34. In section 132 of the principal Act,-

(i) in sub-section (4), in clause (c), in sub-clause (A), in item (II), for the words "ten lakh rupees", the words "five lakh rupees" shall be *substituted;*

(ii) in sub-section (5), for the words, brackets and figure "the Appellate Authority constituted under sub-section (6) in such manner as may be prescribed", the words "the Appellate Tribunal in such manner and on payment of such fee as may be prescribed" shall be *substituted;*

(iii) sub-sections (6), (7), (8) and (9) shall be *omitted.'*. (22)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That clause 34, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

Clauses 35 and 36 were added to the Bill.

Clause 37

Amendment made:

Page 12, lines 25 and 26, *for* "agreed by ninety-five per cent. of the members entitled to vote at the meeting", *substitute*-

"agreed by members-

(a) holding if the company has a share capital, majority in number entitled to vote and who represent not less than ninety-five per cent of such part of the paid-up share capital of the company as gives a right to vote at the meeting; or

(b) having, if the company has no share capital, not less than ninety-five per cent of the total voting power exercisable at the meeting.". (23)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That clause 37, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

Clause 38

Amendments made:

Page 13*, for* lines 6 and 7, *substitute*-

'**38.** in section 137 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) the words and figures "within the time specified under section 403" shall be *omitted;*

(b) in the second proviso, the words and figures "within the time specified under section 403" shall be *omitted;*

(c) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-. (24)

Page 13, line 12, *omit* "listed". (25)

Page 13, *after* line 15, *insert*-

'(ii) in sub-section (2), the words and figures "within the time specified, under section 403" shall be *omitted;*

(iii) in sub-section (3), for the words and figures "in section 403", the word "therein" shall be *substituted.'*. (26)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That clause 38, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 38, as amended, was added to the Bill.
Clauses 39 and 40 were added to the Bill.

(s3/1750/kmr/nk)

Clause 41

Amendment made:

Page 13, *for* lines 21 to 27, *insert-*

"41. In section 141 of the principal Act, in sub-section (3), for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-". (27)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

"That clause 41, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 41, as amended, was added to the Bill.
Clauses 42 to 47 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.28 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.28 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 47A

Amendment made:

Page 15, *after* line 21 , *insert-*

Amendment of section 157

'47 A. In section 157 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), the words and figures, "within the time specified under section 403" shall be *omitted;*

(ii) in sub-section (2), the words and figures, "before the expiry of the period specified under section 403 with additional fee", shall be *omitted.'.* (28)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That new clause 47A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 47A was added to the Bill.

Clause 48

Amendment made:

Page 15, line 27, *after* "178", *insert,* "or a director recommended by the Board of Directors of the Company, in the case of a company not required to constitute Nomination and Remuneration Committee.". (29)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 48, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 48, as amended, was added to the Bill.

Clauses 49 to 58 were added to the Bill.

Clause 59

Amendment made:

Page 18*, for* lines 29 to 36, *substitute-*

"(4) If any loan is advanced or a guarantee or security is given or provided or utilised in contravention of the provisions of this section,-

(i) the company shall be punishable with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees;

(ii) every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees; and

(iii) the director or the other person to whom any loan is advanced or guarantee or security is given or provided in connection with any loan taken by him or the other person, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees, or with both.". (30)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 59, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 59, as amended, was added to the Bill.

Clause 60

Amendments made:

Page 18, *omit* line 38. (31)

Page 19, line 10, *after* "section", *insert,* ", except sub-section (1),". (32)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 60, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 60, as amended, was added to the Bill.
Clauses 61 to 63 were added to the Bill.

(t3/1755/gm-sk)

Clause 64

Amendment made:

Page 19, *for* lines 43 and 44, *substitute*—

'64. In Section 196 of the principal Act,-

(a) in sub-section (3), in clause (a), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that where no such special resolution is passed but votes cast in favour of the motion exceed the votes, if any, cast against the motion and the Central Government is satisfied, on an application made by the Board, that such appointment is most beneficial to the company, the appointment of the person who has attained the age of seventy years may be made.";

(b) in sub-section (4), for the words "specified in that Schedule", the words "specified in Part I of that Schedule" shall be *substituted*.' (33)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That Clause 64, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 64, as amended, was added to the Bill.

Clause 65

Amendments made:

Page 20, *for* line 5 to 7, *substitute*-

"Provided also, that where the company has defaulted in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holders or any other secured creditor,". (34)

Page 20, line 18, *for* "of", *substitute* "or". (35)

Page 20, *for* lines 25 to 27, *substitute*-

"Provided that where the company has defaulted in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holders or any other secured creditor, the". (36)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That Clause 65, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 65, as amended, was added to the Bill.

Clause 66

Amendment made:

Page 20, *for* line 47 to 49, *substitute*-

'(i) in sub-section (3)-

(a) in clause (a), after the words "sold by the company", the words and figures "unless the company is an investment company as referred to in clause (a) of the *Explanation* to section 186" shall be *inserted*:

(b) *after* clause (e), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(f) any amount representing unrealised gains, notional gains or revaluation of assets." (37)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That Clause 66, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 66, as amended, was added to the Bill.
Clauses 67 to 73 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.46 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. "

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.46 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. "

The motion was adopted.

New Clause 73A

Amendment made:

Amendment of section 374	'73A. In section 374 of the principal Act, *after* clause (d), the following proviso shall be *inserted*, namely:- "Provided that upon registration as a company under this Part a limited liability partnership incorporated under the Limited Liability Partnerhip Act, 2008 shall be deemed to have been dissolved under that Act without any further or deed."'. (38)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That new clause 73A be added to the Bill."

The motion was adopted.
New clause 73A was added to the Bill.
Clauses 74 and 75 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.47 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. "

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.47 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. "

The motion was adopted.

New Clause 75A

Amendment made:

Page 21, *after* line 41, *insert*-	
Amendment of section 391	'75A. In section 391 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:- "(2) Subject to the provisions of section 376, the provisions of Chapter XX shall apply *mutatis mutandis* for closure of the place of business of a foreign company in India as if it were company incorporated in India in case such foreign company has raised monies through offer or issue of securities under this Chapter which have not been repaid or redeemed.".'. (39)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That new clause 75A be added to the Bill."

The motion was adopted.
New clause 75A was added to the Bill.

(u3/1800/rsg-rjs)

Clause 76

Amendments made:

(40)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

Page 22, *omit* lines 1 to 20. (41)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 76, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 76, as amended, was added to the Bill.
Clauses 77 and 78 were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House has to be extended up to the passing of the Bill. Do you all agree?

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, the time of the House has to be extended till the passing of the Companies (Amendment) Bill and also for the initiation on the discussion on the IIM Bill. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, it is unfair. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, we will initiate the discussion. We want only five minutes. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I think there is no problem since the Minister wants to speak for only five minutes. There should not be any problem in that.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, he will only initiate the discussion. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is up to him whether he wants one minute, two minutes, or five minutes.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move for suspension of rule 80 (i)

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 42 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 42 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 78A

Amendment made:

Page 22, *after* line 51, *insert* –

Amendment of section 410.

'**78A.** In section 410 of the principal Act, *for* the words, "orders of the Tribunal", the words,

"orders of the Tribunal or of the National Financial Reporting Authority" shall be *substituted*.'. (42)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That new clause 78A be added to the Bill."

The motion was adopted.
New Clause 78A was added to the Bill.
Clauses 79 to 87 were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move for suspension of rule 80(i)

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 43 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 43 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 88

Amendment made:

Page 24, *after* line 22, *insert* –

Amendment of Section 458 "**88.** In section 458 of the principal Act, in sub-section (1), the proviso shall be *omitted.".*

(43)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That new clause 88 be added to the Bill."

The motion was adopted.
New clause 88 was added to the Bill.

Clause 1

Amendment made:

Page 1, line 3, *for* "2016", *substitute* "2017". (2)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Sixty-seventh", *substitute* "Sixty-eighth". (1)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

(w3/1805/rk-rps)

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed. "

The motion was adopted.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, I would request you to kindly take up the next item, the IIM Bill, for consideration.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): How much time will it take?

SHRI ANANTH KUMAR: Only two minutes.

INDIAN INSTITUTETS OF MANAGEMENT BILL

1807 hours

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to declare certain Institutes of management to be institutions of national importance with a view to empower these institutions to attain standards of global excellence in management, management research and allied areas of knowledge and to provide for certain other matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

सर, आईआईएम में आज केवल सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और फेलोशिप मिलती है, वे डिग्री और पीएचडी नहीं दे सकते हैं। इस बिल से ये नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूट होगी और अब वे पीचडी दे सकेंगे। ये हमारे 20 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं और ये विश्व स्तर पर रिकग्नाइज्ड हैं। इससे इनका रिकग्निशन और बढ़ेगा। इसमें दूसरी बात यह है।...(व्यवधान) इसकी जरूरत है। ...(व्यवधान) I would say that you will love it. Today, in IIM there is tremendous Government interference or control. We want to remove that control and this Bill also seeks to do that.

I hope that a good discussion will provide me more inputs. So, I would request that this Bill may be discussed. This in a way is a historical step as the Government will no longer be controlling these institutes. We must trust our best brains. We must trust our best institutes. This is the beginning of that era where we trust our educational institutes and give them freedom and autonomy.

I will continue my speech tomorrow.

HON. CHAIRPERSON: The discussion will continue tomorrow.

The House stands adjourned to meet on Friday, the 28th July, 2017 at 11.00 a.m.

1809 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 28, 2017/Shravana 6, 1939 (Saka).